

बड़े आयोजनों की मेज़बानी करेगा विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला राजस्थान मंडपम

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल एवं आंगंतुक पार्किंग पर दिशा-निर्देश दिए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम एवं यूनिटी मॉल की कार्ययोजना के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय बैठक ली तथा राजस्थान मंडपम बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल एवं आंगंतुक पार्किंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

जयपुर, 16 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की पुख्ता कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि यहां पर बड़े आयोजन सुगमता से हो सकें। शर्मा गुरुवार को जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम एवं यूनिटी मॉल की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम

- मंडपम के साथ बन रहा यूनिटी मॉल, जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद व स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन व विक्रय के लिये वन स्टॉप के रूप में कार्य करेगा।
- राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल के प्रस्तुतिकरण को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता तथा रीको के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा।

स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, संस्कृतिक

और व्यावसायिक आयोजनों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा। देश

एवं विदेशों के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटरों का परीक्षण कर राजस्थान मंडपम में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने यहां विकसित होने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल एवं आंगंतुक पार्किंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में 'मेक इन इंडिया' तथा 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' के तहत, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। यह मॉल जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। इसमें दुकानकारों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये, सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, यहां कॉमन ट्रेनिंग सेंटर, ओपन थिएटर, बिज़नेस मीटिंग हॉल एवं सेमीनार हॉल आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान मंडपम एवं यूनिटी मॉल की प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस दौरान, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, रीको के वरिष्ठ अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन के प्रकरण में केस डायरी तलब

जयपुर, 16 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के निजी आवास के बाहर प्रदर्शन और भीड़ को उत्र करने के मामले में नरेश मीणा के खिलाफ बारां जिले में दर्ज एफआईआर से जुड़ी केस डायरी 20 जनवरी को अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि घटना को लेकर किसी भी व्यक्ति के कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पूर्व में प्रकरण में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों को जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई

■ **कोर्ट ने यह आदेश आरोपी नरेश मीणा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। नरेश मीणा पर आरोप है कि उसने भीड़ को उकसाकर प्रमोद जैन भाया के घर का घेराव करवाया था।**

की जा रही है और उसे अंदेशा है कि इस एफआईआर में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाम दिया जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में मनोज शर्मा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। ऐसे में वे राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। इस पर अदालत ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए मामले की सुनवाई 20 जनवरी को तय की है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सितंबर, 2023 में नरेश मीणा ने अन्य लोगों के साथ तत्कालीन मंत्री प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर घटना दिया था। वहीं बाद में बारां के स्थानीय थाना पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज किया था। नरेश मीणा पर आरोप लगाया गया कि उसने भीड़ को उकसा कर तत्कालीन मंत्री के घर का घेराव किया।

रात ढाई बजे सैफ अली खान पर उनके घर में जानलेवा हमला

हमलावर लूट के इरादे से उनके घर में घुसा और एक करोड़ रु. मांगे



सैफ अली खान

इस बीच दूसरी मेड भी आ गई। हमलावर ने बच्चों की देखभाल करने वाली मेड (नेनी) से एक करोड़ रुपए की डिमांड की। इस दौरान सैफ अली खान भी वहां पहुंचे और अज्ञात आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई।

मेड ने अपने बयान में बताया कि हमले के वक्त घर में 3 महिला और 3 पुरुष नौकर थे। इब्राहिम और सारा अली खान भी उसी बिल्डिंग में आठवीं मंजिल पर ही रहते हैं। वे ऊपर आए और सैफ

- **विरोध करने पर अज्ञात हमलावर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। सैफ के गले, पीठ, हाथ व सिर पर चाकू के 6 घाव लगे हैं, जिनमें से दो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं।**
- **खार के गुरुशरण अपार्टमेंट में सैफ के पलैट में हमलावर सीढ़ियों से दाखिल हुआ और उसी रास्ते भागा।**
- **उसी बिल्डिंग में रह रहे इब्राहिम व सारा अली खान घायल सैफ को आँटो से लीलावती अस्पताल ले गये। कोई इवाइवर मौजूद नहीं था तथा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन किसी को चलाना नहीं आता था।**

पुलिस ने बताया कि सैफ के घर से 3 हाउस मेड को पृथक् पृथक् लिए गए। हाउस मेड ने पुलिस को बताया कि उसे बाथरूम के पास अचानक कोई परछाईं नजर आई उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आयी होंगी, लेकिन उन्हें बाद में शक हुआ तो वह आगे गई। अचानक एक व्यक्ति ने महिला के ऊपर हमला कर दिया और धारदार हथियार दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा।

अली खान को लेकर आँटो में अस्पताल गए घर पर कोई भी इवाइवर मौजूद नहीं था। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाहन किसी को चलाना नहीं आता था, इसलिए सैफ को लेकर आँटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने हमलावरों की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं। क्राइम ब्रांच ने भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित कर दी हैं। क्राइम ब्रांच जांच के लिए सैफ के घर भी पहुंच चुकी है।

अमेरिका की 'शेयर रिसर्च कम्पनी' हिंडनबर्ग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शुरू हुई और इण्डियन सिक्न्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) ने भी जांच शुरू की थी। अडानी शेयरों के अलावा, इस रिसर्च फर्म ने कई अन्य कंपनियों पर भी रिपोर्ट जारी की थीं। यू.एस. सिक्न्यूरिटीज ओवरसाइट समिति,

सिक्न्यूरिटीज एण्ड एक्सचेंज कमिशन (एस.ई.सी.) ने भी इस फर्म की गतिविधियों तथा अपनी रिपोर्टों द्वारा बाजार जोड़-तोड़ करने की जांच शुरू की थी।

हिंडनबर्ग जॉर्ज सोरोस से लिंक की भी जांच हो रही है। हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर आने पर अडानी ग्रुप के स्टॉक व निवेशकों में भारी उत्साह देखा गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयप्रम रमेश ने कहा इसका अर्थ यह नहीं है कि अडानी ग्रुप को बलीतन चिट मिल गई है।

सहारा क्रेडिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दिया। प्रार्थिया ने अवमानना प्रार्थना पत्र में कहा कि उसने 2016 में विपक्षी सोसायटी में 50 हजार रुपए जमा कराए थे। इस राशि की परिवर्तना अर्थात् पर उसे विपक्षी द्वारा 2021 में एक लाख रुपए दिए जाने थे। लेकिन उसने यह राशि नहीं दी। यह मामला उपभोक्ता आयोग में जाने पर प्रार्थिया के पक्ष में 19 जुलाई 2022 को आदेश हुआ। लेकिन विपक्षी सहारा क्रेडिट को अपॉर्टिवट सोसायटी ने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर प्रार्थिया ने आदेश की पालना करवाने के लिए आयोग में अवमानना प्रार्थना पत्र दाखल किया।

दिल्ली वालों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वैष्णव ने कहा कि 8 वीं वेतन आयोग गठित करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया है। वैष्णव ने कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में गठित हुआ था और 2026 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया आयोग के गठन की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू करने से सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

दिल्ली : भाजपा ने 9 नाम और घोषित किये

नयी दिल्ली, 16 जनवरी। भाजपा ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये नौ उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी सूची के अनुसार, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुर और बवाना सुरक्षित सीटों से क्रमशः रविकांत उज्जैन, प्रवीण निमेष और रवींद्र कुमार (इंद्रराज) को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने वजीरपुर से पुनम शर्मा, दिल्ली कैट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, शाहदरा से संजय गोयल और बाबरपुर से अलिन बिष्ट को प्रत्याशी घोषित किया है।

कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिये दो गारन्टियों की घोषणा की

नयी दिल्ली, 16 जनवरी। कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दो गारन्टियों की घोषणा की, जिनमें पहली गारंटी 'मुफ्त बिजली योजना' और दूसरी गारंटी 'महंगाई मुक्ति योजना' है। कांग्रेस ने मुफ्त बिजली योजना के तहत दिल्लीवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा किया है। वहीं, महंगाई मुक्ति योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर और राशन किट मुफ्त, जिसमें पांच किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम चीनी, एक लीटर तेल, छह किलोग्राम दाल और 250 ग्राम चाय पत्ती मुफ्त में देने का वादा किया है। इन दोनों योजनाओं की घोषणा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवन्त रेड्डी ने की। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, तेलंगाना के मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना से सांसद मल्लू रवि और रघुवीर रेड्डी मौजूद थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस जो वादे करती है, उसे पूरा करती है। मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि दिल्ली में पांच फरवरी को कांग्रेस को वोट देकर चुने, कांग्रेस दिल्ली की जनता की जरूरतों को पूरा करेगी।

'प्लेसेज ऑफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) किया जाये।

राजनैतिक दलों, जिनमें आरजेडी, एआईएमआईएम तथा जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल हैं, ने अलग-अलग याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करे, ताकि साम्प्रदायिक तनाव रुक जायें तथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना सुरक्षित रहे।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच इन सभी याचिकाओं की सामूहिक सुनवाई 17 फरवरी को करेगी।

कर्नाटक कांग्रेस में फिर से नेतृत्व परिवर्तन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नहीं, राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर कर्नाटक की राज्य पार्टी इकाई में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इस समय पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार हैं। परमेश्वर ने गुरुवार को बेंगलुरु में पत्रकारों को बताया कि डीकेएस दो पद- उपमुख्यमंत्री तथा केपीसीसी अध्यक्ष- संभाले हुये हैं तथा इस स्थिति में, उनसे एक ही जिम्मेदारी संभालने की अपेक्षा की जायेगी।

अपना स्वयं का अनुभव बताते हुये उन्होंने कहा कि जब वे केपीसीसी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया था, ताकि पूरा ध्यान पार्टी संचालन की जिम्मेदारी पर दे सकें। उन्होंने कहा, "इस संबंध में निर्णय लेने का काम हाईकमान का है, लेकिन दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करने से व्यक्ति पर दबाव तो रहता ही है। इस बीच, कांग्रेस के लिये गेम-चेन्जर माने जाने

वाले डी.के. शिवकुमार ने गृह मंत्री के इस अप्रत्यक्ष हमले को सहज रूप में नहीं लिया। पार्टी या सरकार में प्राप्त पद में से किसी एक पद से उन्हें हटाये जाने की माँग को खारिज करते हुये, शिवकुमार ने दोहराया कि ये दोनों पद न तो मीडिया की देन हैं और न बाजार से खरीदे गये हैं।

ये काम और योगदान से अर्जित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मीडिया के माध्यम से पदों की माँग नहीं कर सकता। जाहिर है कि शिवकुमार का संकेत स्थानीय मीडिया में दिये गये गृह मंत्री के बयानों की ओर था।

उन्होंने पार्टी हलकों में चल रही उन चर्चाओं और बहसों पर भी कटाक्ष किया, जिनमें से कुछ स्थानीय मीडिया में जगह पा रही है। डी.के. शिवकुमार ने कहा कि केन्द्रीय पार्टी नेतृत्व इन सब मुद्दों पर निर्णय लेगा और यह निर्णय व्यक्ति की मैरिट और उसके योगदान

के आधार पर लिया जायेगा, "सार्वजनिक रूप से दिये जा रहे बयानों" के आधार पर नहीं।

कर्नाटक कांग्रेस में जहाँ नेतृत्व की रस्साकशी चल रही है, वहीं जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी चर्चाओं का केन्द्र बनी हुई है।

मंत्रिमंडल में चर्चा होने के बाद, यह रिपोर्ट जनता के समक्ष कब आयेगी तथा आयेगी भी या नहीं। परमेश्वर ने आशा जताई कि यह रिपोर्ट यथारोप सार्वजनिक की जायेगी। इस बीच, राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धार्थैया तथा उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने पार्टी नेताओं से अनुरोध किया है कि वे पार्टी अनुशासन का पालन करें तथा पार्टी के अंदरूनी मामलों को सार्वजनिक करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पार्टी और उसकी छवि को नुकसान होता है।

शिवकुमार ने कहा, "यह पार्टी केवल शिवकुमार के कारण ही सता में

नहीं आई। यह मेहनत और उस विश्वास का परिणाम है, जो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने हमारे प्रति व्यक्त किया था। हमें इस भरोसे को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना होगा। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को पार्टी है तथा इसका एक लम्बा और मौल्यपूर्ण इतिहास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पद पर रहता है और कौन छोड़ता है, पार्टी में स्वयं को कायम रखने की ताकत है।"

उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को अपनी शिकायतें एवं परेशानियाँ जनता के सामने रखने से बचना चाहिये। पिछले कुछ समय से एक पूर्णकालिक केपीसीसी अध्यक्ष की माँग हो रही है। इस विषय में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, "इस मामले का स्पष्टीकरण देना मेरा काम नहीं है। यह काम एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे का है। इस विन्बु से संबंधित प्रश्न उनके पास जाने चाहिये।"

सबसे पहले लाइफ इन्शोरेंस

आजीवन गारंटीड मासिक आय की योजना बनायें हमारे बड़े हुए वार्षिकी दरों के साथ

एक वर्ष की न्यूनतम स्थगितकरण अवधि के बाद वार्षिकी शुरू हो सकती है

2 वर्ष

3 वर्ष

4 वर्ष

5 वर्ष

जीवन शांति

UIN-512N338V07 • Plan No. 758

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना

अधिकतम स्थगितकरण अवधि वार्षिकी योजना के लिए

ऑनलाइन भी उपलब्ध

निश्चित वार्षिकी दरें पॉलिसी के प्रारंभ से

अनेक वार्षिकी विकल्प

बढ़ता हुआ मृत्यु लाभ आस्थगन अवधि के दौरान

हमारा वॉट्सएप नं. **8976862090**

कहिए 'Hi'

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप

विजिट करें: licindia.in

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/विजिट करें www.licindia.in या अपने शहर का नाम **56767474** पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें:

LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

थोड़ेपनी वाले फोन कॉल तथा बड़े/भाग्य प्रस्तावों से सावधान रहें- आइआईसीआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की विक्री, बीमन की घोषणा या प्रीमियम के निवेश, राशियाँ लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियाँ में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या सभाजित प्राइवो को ऐसे फोन कॉलस मिलें, वे कृपया पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज करें। कृपया विक्री के सम्पान से पहले विक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें।